इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 730

29 नवम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग का लक्ष्य से चूकना

730. श्री भुपेन्द्र यादव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग 2011-12 के लिए अपने उत्पादन लक्ष्य से 40 प्रतिशत तक चूक गया है और सरकार ने अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा 2016-17 तक के लिए संशोधित कर दी है;

(ख) क्या सरकार नई इस्पात नीति शुरू करने की परिकल्पना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रमुख चालू निवेशों के विलंबित होने के मद्देनजर इस्पात उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रवृत्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (ग): पिछले कई वर्षों से इस्पात के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 में क्रूड स्टील का उत्पादन 70.67 एमटी से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 73.79 एमटी हो गया है। वर्तमान राष्ट्रीय इस्पात नीति का गठन वर्ष 2005 में किया गया था। तथापि, विश्व और घरेलू दोनों स्तरों पर बदले हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस्पात मंत्रालय ने एक नई राष्ट्रीय इस्पात नीति का गठन करने का निर्णय लिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में इस्पात उद्योग के विकास एवं प्रगति से संबंधित अनेक मुद्दों का निपटान किया जाएगा।

(घ) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। अत: अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए संयुक्त उद्यम/समझौते/अधिग्रहण/प्रत्यक्ष निवेश करने का निर्णय जिसके परिणामस्वरूप देश में एफडीआई का प्रवाह होता है उद्यमियों द्वारा उनकी समीक्षा के आधार पर लिया जाता है। ऐसे मामलों में सरकार ऐसे नीतिपरक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव करती है जो इस अंतर प्रवाह को सुविधा प्रदान करे और प्रोत्साहित करे।

****